



2026:AHC:198390-DB

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 12459 of 2026

Pooja Devi

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 3 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Vinay Kumar
Counsel for Respondent(s)	:	G.A.

Court No. - 49

HON'BLE AJAY BHANOT, J.

HON'BLE DIVESH CHANDRA SAMANT, J.

Heard Shri Vinay Kumar, learned counsel for the petitioner and learned AGA for the State.

The petitioner is aggrieved by the order dated 09.03.2026 passed by the District Magistrate, Firozabad in purported exercise of powers under Section 16 of the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986 (hereinafter referred to as 'Gangsters Act'). The properties of the petitioner were attached by order dated 22.7.2025 rendered under Section 14(1) of Gangsters Act. Aggrieved by the aforesaid order, the petitioner moved an application for release of the property under Section 15 of the Gangsters Act. The aforesaid application has been rejected by the impugned order. The operative portion of the order is extracted hereunder:

"उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली का गहनता से परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रभारी निरीक्षक थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं० 160/2025 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद बनाम निर्दोश व अन्य दर्ज किया गया था, जिसमें सुशील कुमार उर्फ सट्टा पुत्र भीमसेन, निवासी सन्तोष नगर गली नं०-9, थाना उत्तर, जनपद फिरोजाबाद अभियुक्त है। अभियुक्त सुशील कुमार उर्फ सट्टा ने वर्ष 2011 में प्रथमवार अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसके विरुद्ध कुल 19 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें लूट करना, बलबा करना, व्यपहरण, बलात्कार,

उद्यापन, आपराधिक अभिप्रास, गृह अतिचार, मारपीट, गाली गलौज, जान से माने की धमकी, जुआ खेलना, अवैध शस्त्र रखना, जान से मारने की कोशिश करना, हत्या करना जैसे गम्भीर अपराध कारित किये गये हैं, जो भारतीय दण्ड संहिता से सम्बन्धित व दण्डनीय है। अभियुक्त सुशील कुमार उर्फ सट्टा के द्वारा अपराध की दुनियों से अर्जित धन से अपनी पत्नी के नाम अचल सम्पत्तियों कय की गई हैं, जिन्हें कुर्क किया गया है। इस प्रकार अभ्यावेदनकर्ती द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2025/02.01.2026 के समर्थन में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उसके द्वारा उक्त सम्पत्ति को इस आय के श्रोत से अर्जित किया गया है। पुलिस रिपोर्ट व विवेचनात्मक साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा अवैध लाभ हेतु अपराध किये जाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। विपक्षी द्वारा अर्जित की गई सम्पत्ति के श्रोतों को साबित करने में अभ्यावेदनकर्ती पूर्णतः असफल रही है। सम्यक् विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2025, स्थिर रहने योग्य है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 19.12.2025/02.01.2026 निरस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।"

Section 16(1) of Gangsters Act is being extracted herein under for ease of reference:

"16(1). Where no representation is made within the period specified in sub-section (1) of Section 15 or the District Magistrate does not release the property under sub-section (2) of Section 15 he shall refer the matter with his report to the Court having jurisdiction to try an offence under this Act."

As per the mandate of Section 16(1) of Gangsters Act, the District Magistrate in the event of declining to release the attached property on an application under Section 15(1) of Gangsters Act is liable to refer the matter to the court having jurisdiction. In the instant case no such reference has been made by the District Magistrate.

Learned AGA on the basis of instructions does not dispute the aforesaid fact.

The impugned order is in the teeth of the Section 16(1) of the Gangsters Act. The impugned order is liable to be quashed and is quashed.

The matter is remitted to the District Magistrate,

Firozabad with a direction to decide the representation of the petitioner for release of property afresh as per law within a period of two months from the date of receipt of a certified copy of this order.

The writ petition is allowed to the extent indicated above.

**September
22, 2026**

Vandit

(Divesh Chandra Samant,J.) (Ajay Bhanot,J.)